

## भारत के बाह्य क्षेत्र की सुदृढ़ता के आयाम

### शक्तिकान्त दास

अंतर्राष्ट्रीय वातावरण बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है। वैश्विक विकास धीमा हो रहा है और दुनिया भर के केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति को सहज बनाकर इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं; लेकिन अभी तक कोई मंदी नहीं आई है। व्यापारिक युद्धों ने विश्व व्यापार को संकुचित कर दिया है और तकनीकी तथा मुद्रा युद्ध का रूप लेने का भय है किसी को भी कोई महत्वपूर्ण लाभ होने का प्रमाण नहीं है। निवल वस्तु आयातकों को संपार्श्विक लाभ और पण्य निर्यातकों के लिए व्यापार घाटे की शर्तों के साथ इस बीच वैश्विक पण्यों की कीमतें कम हो गई हैं। हालांकि सऊदी तेल पर ड्रोन हमलों के कारण परिणामी घटनाक्रम अभी भी उभर रहे हैं। सुरक्षा के छिटपुट उपाय पूंजी प्रवाह को उभरते हुए बाजारों से उन्नत अर्थव्यवस्था आस्तियों की तरफ ले जा रहे हैं; लेकिन निगेटिव यील्डिंग बॉन्ड का विस्तार बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है जिससे वित्तीय स्थिरता को संभावित खतरा है।

### शक्तियां और कमजोरियां

इस प्रतिकूल वातावरण में भारत के बाह्य क्षेत्र ने सुदृढ़ता और व्यवहार्यता का प्रदर्शन किया है। चालू खाता घाटा औसतन पिछले 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद का 1.4 प्रतिशत है और पोर्टफोलियो प्रवाह के लिए जोखिम-पर-जोखिम अस्थिरता प्रदान करने वाले वैश्विक स्पिलओवर के बावजूद आसानी से वित्तपोषित है। 13 सितंबर 2019 को विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर 429 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो कि आयात के 10 महीने के करीब या 1 साल तक के अवशिष्ट परिपक्वता के 21 महीने के ऋण को कवर करने के लिए पर्याप्त था। भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए एक पसंदीदा विकल्प बनी हुई है और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं # के लिए शीर्ष 10 स्थानों में एक है। नेट एफडीआई अप्रैल-जुलाई 2019 में 2018-19 की

\* श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक 19 सितंबर 2019 को मुंबई में ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2019 में।

# स्रोत: एफडीआई रिपोर्ट, फाइनेंशियल टाइम्स, 2018.

इसी अवधि में 11.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक 18.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

1990 में सामने आई बाह्य भुगतान कठिनाइयों, जिसने व्यापक संरचनात्मक समायोजन और सुधारों को गति दी, के बाद से बाह्य ऋण प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जीडीपी के 19.7 प्रतिशत पर बाह्य ऋण का स्तर और ऋण सेवा अनुपात (वर्तमान आय के अनुपात के रूप में मूलधन भुगतान और ब्याज भुगतान) जीडीपी के 6.4 प्रतिशत पर उभरते हुए बाजारों में सबसे कम है। यह विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार दुनिया के बाह्य रूप से सबसे कम ऋणी देशों में भारत को रखता है। बाह्य देयताओं के व्यापक उपाय के संदर्भ में - निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति (एनआईआईपी) जिसमें ऋण और इक्विटी देयताएँ दोनों शामिल हैं, विदेशी आस्तियों का निवल - भारत का एक्सपोजर मार्च 2015 के अंत में 18.3 प्रतिशत के स्तर से घटकर मार्च 2019 के अंत में जीडीपी का 15.9 प्रतिशत हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार में मार्च 2014 के अंत में, क्रमशः 68.2 प्रतिशत और 89.3 प्रतिशत से बढ़ कर मार्च 2019 के अंत में बाह्य ऋण का 76 प्रतिशत और एनआईआईपी का 94.6 प्रतिशत था। अवशिष्ट परिपक्वता के लघु अवधि के ऋण मार्च 2013 के अंत में 59 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से घटकर मार्च 2019 की समाप्ति पर में विदेशी मुद्रा भंडार के 57 प्रतिशत तक हुए। मूल परिपक्वता वाले अल्पकालिक ऋण कुल बाह्य ऋण का मुश्किल से 20 प्रतिशत है।

स्वस्थ विकास भारत की अंतर्निहित बुनियाद की सहज ताकत हैं। वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात तथा जीडीपी के अनुपात से मापी जाने वाली अर्थव्यवस्था के खुलेपन का स्तर 1990 के दशक की पहली छमाही के 20 प्रतिशत से बढ़कर 2014-19 के पांच साल की नवीनतम अवधि में 44 प्रतिशत हो गई है। विश्व निर्यात में भारत के व्यापारिक निर्यात का हिस्सा 1990 के 0.5 प्रतिशत से बढ़कर 2018 में 1.7 प्रतिशत हो गया है।

घरेलू उत्पादन में सेवाओं के बढ़ते हुए योगदान के साथ भारत की सेवाओं का निर्यात पिछले दो दशकों में तेजी से बढ़ा है। वास्तव में भारत की सेवाओं के निर्यात ने व्यापारिक निर्यातों की तुलना में वैश्विक आघातों के लिए उच्च स्तर की आघात सहनीयता दिखायी है। 81.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर निवल

सेवाओं की निर्यात ने 2018-19 में भारत के व्यापार घाटे के 45 प्रतिशत को वित्तपोषित किया है। व्यापार सेवाओं के क्षेत्र में दुनिया के सॉफ्टवेयर निर्यात के लगभग 12 प्रतिशत हिस्से के साथ भारत सॉफ्टवेयर निर्यात और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाओं में विश्व में अग्रणी है। भारत का आईटी सेक्टर, जिसने 2018-19 में शुद्ध निर्यात के माध्यम से 78 बिलियन अमेरिकी डॉलर कमाया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स सहित नई तकनीकों में छलांग लगा रहा है। भारतीय प्रवासी, दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और इसे दर्शाते हुए भारत वर्तमान में विदेशों में काम कर रहे भारतीयों से दुनिया में सबसे अधिक आवक प्रेषण प्राप्त करता है। इसके साथ-साथ गैर निवासी जमाराशियों में वृद्धि ने वर्षों में भुगतान संतुलन में स्थिर और विश्वसनीय सहायता प्रदान की है। सकल पूंजीगत अंतर्गत और आउटफ्लो और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात से मापा जाने वाला वित्तीय खुलापन 1990 की पहली छमाही में 15 प्रतिशत से तीन गुना बढ़ कर 2014-19 के दौरान 45 प्रतिशत हो गया है।

इन उपलब्धियों के होते हुए भी ऐसी कई चिंताएँ हैं जिन्होंने बाह्य क्षेत्र प्रबंधन के संचालन में महत्वपूर्ण स्थान लिया हुआ है। सबसे पहले विश्व व्यापार में मंदी के बोझ के कारण व्यापार निर्यात ने गति खो दी है। 2013-18 (UNCTAD, 2019) के दौरान निर्यात की मात्रा में औसतन 4.2 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में भारत की निर्यात वृद्धि उसी अवधि में 2.2 प्रतिशत तक कमजोर हुई है – कई उभरती और उन्नत बाजार अर्थव्यवस्थाओं जैसे ही - क्योंकि इकाई के मूल्य में गिरावट ने इसे दुष्प्रभावित किया है। वैश्विक माँग में मंदी के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के हमारे निर्यात पर भी असर पड़ा है - वो कुल व्यापार निर्यात का 14 प्रतिशत है। दूसरा, घरेलू माँग में गिरावट ने आयातों, विशेष रूप से गैर-तेल गैर-सोने के आयातों को संकुचित किया है और इससे मध्यवर्ती, पूंजीगत वस्तुओं और प्रौद्योगिकी का इनफ्लो कम हो गया है जो हमारी अवसंरचनाएँ और उद्योग के आधुनिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा, पोर्टफोलियो प्रवाह, जो एक सामान्य वर्ष में बाह्य वित्तपोषण का लगभग औसतन 23 प्रतिशत रहता है, 2018-19 में 0.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल आउटफ्लो के साथ अत्यधिक अस्थिर हो गया है। 2019-20 के दौरान अब तक (13 सितंबर तक) पोर्टफोलियो इक्विटी आउटफ्लो 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था लेकिन एक साल

पहले इसी अवधि में 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम था। हालांकि ऋण बाजार में 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इनफ्लो ने राहत दी है। इसके अलावा, पोर्टफोलियो कैपिटल मूवमेंट वैश्विक स्पिलओवरों का माध्यम बन गया है जो कि घरेलू इक्विटी, ऋण और विदेशी मुद्रा बाजार, और आस्ति की कीमतों पर प्रभाव डालता है। फिर भी मैंने बताया सकारात्मक सुविधाओं से स्थिर भारत के बाह्य क्षेत्र के अंतर्निहित सुदृढ़ता ने इन आघातों को दूर से किया और घरेलू अर्थव्यवस्था को रोधक सुरक्षा प्रदान की।

### बाह्य क्षेत्र का प्रबंधन

इस पृष्ठभूमि में मैं भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा भारत की बाह्य स्थिति को मजबूत करने हेतु और इस परीक्षा के समय में विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था की क्षमता में सुधार के प्रयोजन से किए गए कई हालिया पहलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

### निर्यात

भुगतान संतुलन की स्थिति के लिए निर्यात महत्वपूर्ण है। अंतिम विश्लेषण से पता चलता है कि, वस्तु और सेवा के निर्यात से मिलनेवाली विदेशी मुद्रा आय तथा ऐसी सेवाएँ जिनके कारण देयताएं चूकाने की और आयात क्रय शक्ति मिलती है के लिए इक्विटी के साथ-साथ कर्ज के रूप में देयताएं पर्याप्त नहीं हैं। इन वर्षों में नीति का प्रयास उत्पादों और गंतव्यों, दोनों के संदर्भ में भारत के निर्यात प्रोफाइल में व्यापक विविधीकरण को लाना है। विशेष रूप से, उत्पाद विविधीकरण ने भारत को ब्रिक्स साथियों के सापेक्ष अपनी निर्यात बास्केट को व्यापक बनाने और व्यापार के आघातों के लिए इसकी भेद्यता को कम करने में सक्षम बनाया है। विविधीकरण के अलावा भारत अब इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स जैसे उभरते हुए उत्पादों का निर्यात कर रहा है जिसके लिए वैश्विक स्तर पर माँग बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के स्मार्ट फोन खंड में चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम से मिली हुई गति से भारत ने एक आयातक की भूमिका से खुद को निर्यातक के रूप में बदल दिया है।

आगे बढ़ते हुए, कई पहल किए गए हैं और अन्य नियमित आधार पर शुरू हो रहे हैं ताकि निर्यात उद्योगों को उत्पादकता और अत्याधुनिक प्रतिस्पर्धा हासिल करने में सक्षम बनाया जा

सके। इनमें निर्यात सुविधाओं का उन्नयन, भारतीय किसानों और उनके उत्पादों का वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकरण और व्यापार सुविधा के उपाय भी शामिल हैं। हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में इनपुट टैक्स क्रेडिट की इलेक्ट्रॉनिक वापसी सहित करों और शुल्क (ड्यूटी) की प्रतिपूर्ति के प्रयास चल रहे हैं। फरवरी 2018 से आईटी, पर्यटन और आतिथ्य तथा चिकित्सा सेवाओं सहित 12 'चैंपियन' सेवा क्षेत्रों के लिए एक कार्य योजना विकसित की गई है। रिज़र्व बैंक और सरकार सक्रिय रूप से ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के प्रचार में लगे हुए हैं जो कि व्यापार और सेवाओं, दोनों के निर्यात को बढ़ावा देंगे। ये सभी कदम निर्यात के लिए अधिक अनुकूल माहौल तैयार करना चाहते हैं।

### पूंजी प्रवाह

पूंजी प्रवाह के संबंध में भारत ने प्रगतिशील उदारीकरण का दृष्टिकोण अपनाया है, लेकिन वित्तीय बाजारों के विकास सहित घरेलू स्थिति की वास्तविकताओं के लिए अंशकित दृष्टिकोण रखा है। एक विस्तारित निवेशक आधार के विनिमय दर जोखिम प्रबंधन के लिए लिखतों की एक विविध शृंखला सामने आयी हैं। भारत की पदानुक्रमित नीति दृष्टिकोण - ऋण प्रवाह पर इक्विटी प्रवाह को प्राथमिकता देना, और इक्विटी प्रवाह के अंतर्गत पोर्टफोलियो प्रवाह पर एफडीआई प्रवाह को प्राथमिकता देना, और सकल ऋण प्रवाह के अंतर्गत अल्पकालिक प्रवाह पर दीर्घकालिक ऋण प्रवाह को प्राथमिकता देना- ने पूंजी प्रवाह की संरचना को प्रभावित किया है।

इक्विटी प्रवाह की ओर मुड़ते हुए, भारत को एक आकर्षक निवेश स्थान बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई नीति को लगातार उदार बनाया गया है। हाल के वर्षों में रक्षा, निर्माण विकास, व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स, पावर एक्सचेंज, बीमा, पेंशन, वित्तीय सेवाएं, आस्ति पुनर्निर्माण, प्रसारण और नागरिक उड्डयन क्षेत्रों को खोला गया है। बीमा मध्यस्थों में 100 प्रतिशत एफडीआई की भी अनुमति दी गई है। अगस्त 2019 में एकल-ब्रांड खुदरा व्यापार में एफडीआई मानदंडों को और अधिक उदार बनाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग और कोल माइनिंग में ऑटोमैटिक रूट के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी गई है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के संबंध में, एक निवेशक-अनुकूल माहौल बनाने और अधिक अनुमानित नीति वातावरण बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। एफपीआई सीमा को अब मध्यम अवधि ढांचे के तहत छमाही आधार पर संशोधित किया जा रहा है। नगरपालिका बांड में राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के लिए निर्धारित सीमा के भीतर एफपीआई की अनुमति दी गई है। एक स्वैच्छिक अवधारणा मार्ग (वीआरआर) के तहत एफपीआई को और ज्यादा परिचालन सुदृढ़ता प्रदान की गयी है जो निवेशकों को उनकी मुद्रा और ब्याज दर के जोखिमों का प्रबंधन करने की अनुमति देते हुए जी-सेक, एसडीएल, ट्रेजरी बिल और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश की सुविधा देता है। वीआरआर योजना के लिए प्रारंभिक प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है। केंद्रीय बजट 2019-20 में एफपीआई के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड को आसान बनाने का और शेयर बाजारों में निर्बाध निवेश के लिए एफपीआई मार्ग के साथ गैर-निवासी भारतीय (एनआरआई) पोर्टफोलियो मार्ग को मिलाने का प्रस्ताव दिया गया था। भारतीय संस्थाओं को वैश्विक स्कैन और उपस्थिति देने के लिए बाह्य प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो निवेश को भी लगातार उदार बनाया गया है।

दो ट्रेक: विदेशी मुद्रा द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी); और रूपये द्वारा डेनोमिनेटेड ईसीबी के तहत बाह्य उधार मानदंडों को भी सरल बनाया गया है। एफडीआई प्राप्त करने के लिए पात्र सभी संस्थाओं यथा समष्टि वित्त गतिविधियों में संलग्न पंजीकृत संस्थाएँ, पंजीकृत समितियाँ / ट्रस्ट / सहकारी और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए पात्र उधारकर्ताओं की सूची का विस्तार किया गया है। जीडीपी के 6.5 प्रतिशत पर ईसीबी के बकाया स्टॉक के लिए एक नियम-आधारित गतिशील सीमा लागू है। ईसीबी मार्ग के तहत रूपये मूल्यवर्ग वाले बांड या मसाला बॉन्ड घरेलू कंपनियों को विनिमय दर के जोखिम को हेजिंग की आवश्यकता के बिना अंतरराष्ट्रीय बाजारों से उधार लेने का अवसर प्रदान करते हैं। स्वचालित मार्ग के तहत प्रति वित्तीय वर्ष 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर या ईसीबी की अनुमति है। हाल ही में, ईसीबी से संबंधित अंतिम-उपयोग प्रतिबंधों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं, सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों और रूपया ऋणों

<sup>1</sup> केंद्र सरकार के प्रतिभूतियों (जी-सेक), राज्य विकास ऋण (एसडीएल) और कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफपीआई निवेश की सीमाएं वर्तमान में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रतिभूतियों के संबंधित बकाया स्टॉक का 6 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 9 प्रतिशत निर्धारित हैं।

की चुकौती हेतु विशिष्ट पात्र उधारकर्ताओं के लिए भी छूट दी गई है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 3 से 5 वर्ष की न्यूनतम परिपक्वता अवधि के ईसीबी के लिए अनिवार्य हेजिंग की आवश्यकता पहले के 100 प्रतिशत से घटाकर 70 प्रतिशत कर दी गई थी। अप्रैल-जुलाई 2019 में ईसीबी का निवल संवितरण बढ़कर 7.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि 2018-19 की इसी अवधि में 0.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवल चुकौती हुई थी।

### विनिमय दर

निष्कर्ष देने से पूर्व रुपये की विनिमय दर के बारे में कुछ कहना उचित ही है। पिछले कुछ सालों में विनिमय दर में मुख्य रूप से वैश्विक स्पिलओवर द्वारा लगाए गए विचारणीय अस्थिरता के साथ बड़े पैमाने पर दोतरफा हलचल देखी गई है। 2019-2020 में अभी तक रुपये ने एक संकीर्ण सीमा में कारोबार किया है जो पहली तिमाही में मामूली मूल्यवृद्धि के साथ अगस्त और सितंबर के पहले पखवाड़े में मूल्यहास की ओर संकेत करती है जिसका मुख्य कारण 14 सितंबर 2019 को सउदी तेल सुविधाओं पर ड्रोन आक्रमण रहा है। जुलाई 2019 की अपनी बाह्य क्षेत्रीय रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने मूल सिद्धांतों के साथ मुद्राओं के मेल का आकलन करने के लिए मॉडल का एक समूह बनाया। आईएमएफ आरईआर अंतर को रुपये के लिए, शून्य होने का अनुमान लगाता है, जो यह दर्शाता है कि मुद्रा काफी मूल्यवान है और मोटे तौर पर मूल सिद्धांतों के अनुरूप है। भारत की विनिमय दर व्यवस्था आघात सहनीय और बाजार संचालित है जिसमें विनिमय दर मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। रिजर्व बैंक के पास विनिमय दर के स्तर के लिए कोई लक्ष्य या बैंड नहीं है। हस्तक्षेपों का उद्देश्य अनुचित अस्थिरता का प्रबंधन करना है। यह पिछले दो वर्षों के दौरान आयोजित दो-पक्षीय हस्तक्षेपों में परिलक्षित होता है 2017-18 में निवल खरीद के बाद 2018-19 में निवल बिक्री। वास्तव में, यह इस सुदृढ़ता की मान्यता है कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने मुद्रा हेरफेर से संबंधित निगरानी से भारत को हटा दिया है।

### निष्कर्ष

यद्यपि इस मोड़ पर कुछ नकारात्मक जोखिमों और बढ़ गयी हैं, कुल मिलाकर बाह्य क्षेत्र के लिए भारत का दृष्टिकोण सतर्क आशावाद का है। उनमें से वैश्विक मंदी का गहरा होना और व्यापार

और भू-राजनीतिक तनाव का बढ़ना सबसे महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। अस्थिर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें भी व्यापार और प्रेषण चैनलों के माध्यम से चालू खाता शेष की व्यवहार्यता के लिए संभावित जोखिमों को बनाए रखती हैं। फिर भी ऐसी अंतर्निहित ताकतें हैं जो बाह्य क्षेत्रों को इन जोखिमों से बचाने के लिए बनाई जा सकती हैं। नए निर्यात मार्केट और नए क्षेत्रों की तलाश जारी रहनी चाहिए ताकि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की बदलती गतिशीलता के लाभ प्राप्त किए जा सकें। भारतीय आईटी कंपनियों को अपने तुलनात्मक लाभ को सुधारने के लिए बाजार विविधीकरण में तेजी लाने और नए कौशल और प्रौद्योगिकियों में निवेश करने की आवश्यकता है। रेमिटेन्स और नॉन-रेजिडेंट डिपॉजिट मध्यम अवधि के लिए शॉक-एब्जॉर्बर बने रहने की संभावना है और इसे प्रेषित / जमा करने में आसानी और लेनदेन की लागत को कम करने सहित सफलतापूर्वक संवर्धित की जानी चाहिए।

अंततः बाह्य क्षेत्र की ताकत घरेलू मैक्रो-फंडामेंटल्स से प्राप्त होती है। निवेशकों और बाजारों को इन क्षेत्रों पर निरंतर ध्यान देने के साथ विश्वसनीय रूप से आश्वस्त होना चाहिए ताकि समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता बनाई रखी जा सके। साथ ही, हमें उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों को बरकरार रखना होगा। अति महत्वपूर्ण उद्देश्य द्वारा चालू खाता घाटे को स्थायी सीमा के भीतर रखना चाहिए और ऋण और इक्विटी प्रवाह के विवेकपूर्ण मिश्रण द्वारा वित्तपोषित किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, वैश्विक वातावरण चुनौतीपूर्ण है लेकिन यह अवसर भी प्रदान करता है। आईएमएफ के आकलन के अनुसार 2020 में वैश्विक वृद्धि में भारत का योगदान छठवाँ रहेगा। व्यापार युद्ध नए व्यापार पुनर्वास के मार्ग प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि भारत के लिए पैमाने और दायरे की अर्थव्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से अनुकूल प्रतीत होता है। भारतीय उद्यमशीलता, रुपया और हमारे लोग उत्तरोत्तर लेकिन अनवरत रूप से अंतरराष्ट्रीय हो रहे हैं। 2018 के बाद से भारत की कामकाजी जनसंख्या आयु निर्भर जनसंख्या से अधिक हो गई है, और यह जनसांख्यिकीय लाभ 2055 तक रहने की उम्मीद है। इस उपलब्धि में बाह्य अतिसंवेदनशील क्षेत्रों पर एक करीबी और निरंतर सतर्कता के साथ विवेकपूर्ण बाह्य क्षेत्र प्रबंधन महत्वपूर्ण बन जाता है और इसपर भारिबैं का विशेष ध्यान बना रहेगा।

धन्यवाद